मृदुला अवस्थी और अन्य

बनाम

दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य

27 अप्रैल, 1988

[रंगनाथ मिश्रा और मुरारी मोहन दत्त, न्यायाधिपतिगण]

व्यावसायिक महाविद्यालय-चिकित्सामहाविद्यालय-स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम-दिल्ली विश्वविद्यालय में 1988 से तीन वर्षीय पी. जी. डिग्री और दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को अपनाने के लिए प्रवेश-एक अस्थायी उपाय के रूप में पुरानी प्रणाली 1988 के शैक्षणिक सत्र के लिए जारी रही, केवल एक वर्ष की हाउसमैनशिप वाले उम्मीदवारों को अयोग्य बना दिया गया वरिष्ठ और फ्रेशर्स दोनों के लिए सामान्य चयन सूची-की वैधता-निर्देश जारी किए गए।

डॉ. दिनेश कुमार और अन्य बनाम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, और अन्य [1987] 4 एससीसी 459 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में एकरूपता के संबंध में, प्रतिवादी नंबर 1- दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर डिग्री के लिए तीन साल का पाठ्यक्रम और 1988 का शैक्षणिक सत्र से शुरू डिप्लोमा के लिए दो साल का पाठ्यक्रम अपनाने का फैसला किया।

हालाँकि, उन अभ्यर्थियों/छात्रों की कठिनाई को कम करने की दृष्टि से, जिन्होंने पहले ही गृह कार्य पूरा कर लिया था और एक अस्थायी प्रावधान के रूप में, दो साल में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने के हकदार बन गए थे - प्रतिवादी-विश्वविद्यालय ने इस अभ्यास को 1988 से पहले एक वर्ष तक प्रचलित जारी रखने का निर्णय लिया। इसने एक ऐसी योजना विकसित की, जिसके तहत, एक वर्ष की हाउसमैनशिप पूरी करने वाले छात्र के लिए पिछले वर्ष में उपलब्ध स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और डिप्लोमा पाठ्यक्रम की सीटों की संख्या को अछूता छोड़ दिया गया था। एक संक्रमणकालीन प्रावधान के रूप में, विश्वविद्यालय केवल 1988 सत्र के लिए 75% कोटा तय करने पर सहमत हुआ। योजना के एक नोट के अनुसार, जिन उम्मीदवारों ने एक वर्ष की अवधि के लिए हाउस जॉब/जूनियर रेजीडेंसी की थी, वे 3 साल की स्नातकोत्तर डिग्री और 2 साल के स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं थे।

हालाँकि, विवरणिका में दोनों श्रेणियों के लिए एक सामान्य चयन परीक्षा निर्धारित की गई थी।

उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं का एक सेट दायर किया गया था, जिसमें विश्वविद्यालय की योजना को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि जब एक चयन परीक्षा होती है, तो योग्यता प्रबल होनी चाहिए और योजना द्वारा बताए गए तरीके से वर्गीकरण खराब था।

उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश दिया जिसमें विश्वविद्यालय को सामान्य चयन परीक्षा में निर्धारित योग्यता के आधार पर चयन पूरा करने की आवश्यकता थी।

रिट याचिकाओं और उच्च न्यायालय से स्थानांतरित कुछ मामलों का निस्तारण करते हुये, अभिनिर्धारित किया

वरिष्ठ जो पहले ही एक वर्ष की गृहकार्य कर चुके हैं और नए लोग दो श्रेणियों में आते हैं और उन्हें समान नहीं कहा जा सकता है। यदि विश्वविद्यालय ने इन दोनों श्रेणियों के लिए एक सामान्य चयन परीक्षा निर्धारित नहीं की होती तो तुलनात्मक योग्यता परीक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि चयन परीक्षा की मेरिट सूची का पालन किया जाता है, तो अधिक वरिष्ठ प्रवेश के हकदार होंगे और आरक्षण की योजना काम नहीं करेगी। [765 एफ-जी]

जबकि उच्च पाठ्यक्रम में चयन इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में योग्यता के आधार पर होना चाहिए, पूरी तरह से एक अस्थायी उपाय तक ही सीमित है, स्थिति को पहले सिद्धांतों द्वारा नहीं बल्कि विशेष रूप से कुछ हद तक सूचित व्यावहारिक तदर्थ द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न नहीं होगी [766 डी]

नए और वरिष्ठों के प्रतिद्वंद्वी दावों के कारण पैदा हुए गतिरोध का एक मोटा और तैयार समाधान होना चाहिए - फिर भी मनमाना नहीं और यथासंभव स्वीकार्य और संतोषजनक। [766 एफ]

वरिष्ठ के लिए कुछ और सीटें उपलब्ध कराने की दृष्टि से, प्रतिवादी विश्वविद्यालय को प्रत्येक विशेषज्ञता में एक सीट सृजित करनी चाहिए। इस प्रकार, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 75% सीटों के अलावा 21 अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी। नए लोगों के लिए बनाई गई आरक्षित सीटों में से 21 सीटें, हर विशेषता में से एक होने के कारण, हटाकर वरिष्ठों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस प्रकार, वरिष्ठ समूह को अलग रखते हुए, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुल मिलाकर 42 सीटें परस्पर योग्यता के आधार पर भरी जाएंगी। 1766 जी-एच; 767 ए-बी]

केंद्र सरकार को फंड के लिए आवश्यक प्रावधान करना चाहिए। भारतीय चिकित्सा परिषद आवश्यकताओं में छूट देकर आवश्यक आवास प्रदान कर सकती है। [767 डी]

डॉ. दिनेश कुमार बनाम मोतीलाल नेहरू कॉलेज, इलाहाबाद एवं अन्य, [1987] 4 एससीसी 459, संदर्भित।

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका (सिविल) संख्या 194/1988 आदि आदि।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)।

डी.डी. ठाकुर, टी.एस. कृष्णमूर्ति अय्यर, राजेश मित्रा, सुश्री संतोष कालरा, एच.के. पुरी, आर.एल.रोशन, एस.एस.सभरवाल, एस.के. सभरवाल, और एम.के.डी. नंबूदिरी; याचिकाकर्ताओं के लिए।

पी.पी. राव, एस.एन. काकर, जी. रथ, श्रीमती ए. माथुर, ए. मारियार-पुथम, सी.एम. नैय्यर, डी.एस. नरूला, कैलाश वासुदेव, श्रीमती उमा जैन और पी.के. मेहता; प्रतिवादीगणो के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया:

आदेश

अनुच्छेद 32 के तहत रिट आवेदन और दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थानांतरित रिट याचिकाएं दिल्ली विश्वविद्यालय के तहत वर्ष 1988 के लिए स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए मेडिकल स्नातकों के चयन से संबंधित हैं। डॉ. दिनेश कुमार बनाम मोतीलाल नेहरू कॉलेज, इलाहाबाद और अन्य में, इस न्यायालय ने जहां तक संभव हो पूरे देश में एकरूपता मेडिकल संकाय में स्नातकोत्तर शिक्षा की वांछनीयता पर जोर दिया। इसलिए, इसने उन शैक्षणिक संस्थानों की सराहना की, जिन्होंने पहले वर्ष में हाउस जॉब के साथ तीन साल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के पैटर्न पर स्विच करने के लिए दो साल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के बाद एक साल की घरेलू नौकरी की प्रणाली का पालन किया। 25 सितंबर, 1987 को, इसी मामले में, जब न्यायालय ने 1987 4 एससीसी 459 में प्रकाशित एक आदेश दिया, तो यह

बताया गया कि कुछ राज्यों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एक वर्ष की हाउसमैनशिप के साथ दो साल की अवधि के लिए होता है। अन्य राज्यों में यह तीन वर्ष का पूर्ण कार्यकाल है। इसलिए, इस न्यायालय ने पहले के फैसले में स्वीकार किए गए सिद्धांत के आधार पर एकरूपता लाने की दृष्टि से निर्देश दिया कि 1993 से शुरू होने वाले प्रवेश के लिए केवल एक पैटर्न होगा, अर्थात्, बिना किसी अलग गृहकार्य के तीन साल का एकीकृत पाठ्यक्रम के। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1988 के शैक्षणिक सत्र से स्नातकोत्तर डिग्री के लिए तीन वर्षीय पाठ्यक्रम और डिप्लोमा के लिए दो वर्षीय पाठ्यक्रम को अपनाने का निर्णय लिया। उन उम्मीदवारों/छात्रों की कठिनाई को कम करने की दृष्टि से, जिन्होंने पहले ही इसे पूरा कर लिया था। घरेलू नौकरी और दो साल में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने के हकदार बन गए थे, एक अस्थायी प्रावधान के रूप में, विश्वविद्यालय ने 1988 से पहले प्रचलित अभ्यास को एक वर्ष के लिए जारी रखने का फैसला किया। विश्वविद्यालय ने एक ऐसी योजना विकसित की, जिसमें एक वर्ष की गृहकार्य पूरी करने वाले छात्र के लिए पिछले वर्ष उपलब्ध स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए सीटों की संख्या को अछूता छोड़ दिया गया था। डिग्री कोर्स के लिए ऐसी सीटों की संख्या 198 है और डिप्लोमा कोर्स के लिये ।।। है। इनमें से 25% को अखिल भारतीय चयन के आधार पर भरने के लिए भारत सरकार के निपटान में रखा गया है, विश्वविद्यालय द्वारा भरे जाने के लिए उपलब्ध सटीक संख्या क्रमशः 149

और 84 है। 1988 सत्र के लिए एक संक्रमणकालीन प्रावधान के रूप में, विश्वविद्यालय केवल 75% कोटा (तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम में 139 सीटें और दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 66 सीटें) तय करने पर सहमत हुआ। निम्नलिखित को योजना का एक भाग निर्दिष्ट किया गया था:

"महत्वपूर्ण लेख

जिन उम्मीदवारों ने एक वर्ष की अवधि के लिए हाउस जॉब/जूनियर रेजीडेंसी की है, वे 3 साल की पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री और 2 साल के पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए पात्र नहीं हैं।

हालाँकि, विवरणिका में एक सामान्य चयन परीक्षा निर्धारित की गई थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं का एक सेट दायर किया गया था, जिसमें विश्वविद्यालय की योजना को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि जब एक चयन परीक्षा होती है, तो योग्यता प्रबल होनी चाहिए और योजना द्वारा बताए गए तरीके से वर्गीकरण खराब था। उच्च न्यायालय के समक्ष इस न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा रखा गया कि स्नातकोत्तर डिग्री के लिए उत्कृष्टता की परीक्षा होनी चाहिए और उच्च दक्षता का स्तर बनाए रखा जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश दिया जिसमें विश्वविद्यालय को सामान्य

चयन परीक्षा में निर्धारित योग्यता के आधार पर चयन पूरा करने के लिए कहा गया।

यह विवाद अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय और उन नए छात्रों के बीच है जिन्होंने एक तरफ हाउसमैनशिप नहीं की है और दूसरी तरफ उन वरिष्ठों के बीच है जिन्होंने पहले ही एक साल के लिए हाउसमैनशिप पूरी कर ली है। इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि वरिष्ठ और नवागंतुक दो अलग-अलग श्रेणियों के हैं और उन्हें समान नहीं कहा जा सकता।यदि विश्वविद्यालय ने इन दोनों श्रेणियों के लिए एक सामान्य चयन परीक्षा निर्धारित नहीं की होती, तो तुलनात्मक योग्यता की परीक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि ऐसा नहीं किया गया होता तो शायद उच्च न्यायालय ने अपना निर्देश नहीं दिया होता और जो कठिनाई उत्पन्न हुई है वह उत्पन्न नहीं होती।

नए लोगों और एक साल की गृहकौशल पूरी कर लेने वालों का वर्गीकरण, हालांकि बोधगम्य है, लेकिन 1987 से पहले प्रचलित प्रणाली में पारंपरिक स्थिति को देखते हुए इसका महत्व कम हो जाता है, दोनों समूहों को स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए चयन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए योग्य माना गया। बार के विद्वान सदस्यों ने हमें बताया है कि आने वाले वर्ष में ऊपर निकाले गए अस्थायी नोट के गायब हो जाने के बाद, पुरानी प्रथा फिर से पुनर्जीवित हो जाएगी, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

स्नातकोत्तर अध्ययनरत अभ्यर्थियों के लिए चयन परीक्षा में भाग लेने की कोई सीमा नहीं होने से वे वर्ष-दर-वर्ष असफल होते जाते हैं, किसी सीमा के अभाव में जोखिम लेते रहते हैं। यह निश्चित रूप से एक वांछनीय विशेषता नहीं है और उचित प्राधिकारियों द्वारा इस पर शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए।

यदि चयन परीक्षा की मेरिट सूची का पालन किया जाता है, तो अधिक वरिष्ठ प्रवेश के हकदार होंगे और आरक्षण की योजना काम नहीं करेगी। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि वकील किसे सुविधा कहते हैं (और यह कितना असुविधाजनक था, यह ज्ञात नहीं है), दिल्ली विश्वविद्यालय ने दो श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए एक सामान्य चयन परीक्षा आयोजित करके प्रारंभिक गलती की। जबकि हम इस न्यायालय द्वारा एक से अधिक अवसरों पर व्यक्त किए गए विचार को दोहराते हैं कि उच्च पाठ्यक्रमों में चयन योग्यता के आधार पर होना चाहिए, इस मामले में उत्पन्न होने वाले विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में यह पूरी तरह से अस्थायी उपाय तक ही सीमित है, स्थिति यह है कि पहले सिद्धांतों द्वारा नहीं बल्कि कुछ हद तक सूचित व्यावहारिक तदर्थवाद द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि ऐसी स्थिति दोबारा न हो. फिर दिल्ली विश्वविद्यालय की शुरुआती गलती से कुछ हद तक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी और उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद यह और

बढ़ गई है। उपलब्ध समय बहुत कम है क्योंकि पूरे देश में लागू होने वाली योजना के तहत पाठ्यक्रम 2 मई, 1988 को शुरू होना है।

इस पृष्ठभूमि में हमारा विचार है कि नए और वरिष्ठों द्वारा किए गए प्रतिद्वंद्वी दावों के कारण पैदा हुए गतिरोध का एक मोटा और तैयार समाधान होना चाहिए - फिर भी मनमाना और स्वीकार्य नहीं और यथासंभव संतोषजनक। हमने पाया कि दो वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम में विशेषज्ञता के आधार पर 149 सीटें हैं जबकि तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम में 139 सीटें हैं। सुविधा के लिए हम सूचना बुलेटिन के पृष्ठ 4 पर उपलब्ध विवरण निकालते हैं। यह बताया जा सकता है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुल 270 रिक्तियों (डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम एक साथ) के मुकाबले 1003 उम्मीदवार हैं; और नए छात्रों के लिए दो पाठ्यक्रमों के लिए 205 रिक्तियों की तुलना में 331 उम्मीदवार हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ और सीटें उपलब्ध कराने की दृष्टि से हमने विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित श्री राव को सुझाव दिया कि सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और उन्होंने निर्देशों पर सहमति व्यक्त की है, बशर्ते कि भारत संघ धन मुहैया कराए और मेडिकल काउंसिल समायोजित करने को इस पर सहमत हो। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इसकी 21 विशिष्टताएँ हैं। हम निर्देश देते हैं कि विश्वविद्यालय प्रत्येक विशेषज्ञता में एक सीट बनाएगा और इस प्रकार, 75 प्रतिशत कोटा का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 149 सीटों के अलावा 21 अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी। सीटों की

इस बढ़ी हुई संख्या पर अखिल भारतीय चयन का 25% आरक्षण लागू नहीं होगा। नए लोगों के लिए बनाई गई पुनः-सेवा सीटों में से, प्रत्येक विशेषता से एक होने वाली 21 सीटें हटा दी जाएंगी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। इस प्रकार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुल मिलाकर 42 सीटें उपलब्ध होंगी, जिन्हें वरिष्ठ समूह को अलग रखते हुए परस्पर योग्यता के आधार पर भरा जाएगा।

21 सीटों के निर्माण में भारत संघ द्वारा प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि शामिल होगी। इसके लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की मंजूरी की भी आवश्यकता होगी और गाइड-छात्र अनुपात में बदलाव की अनुमति देने की भी आवश्यकता होगी। चूँकि यह एक वर्ष के लिए है और इसकी पुनरावृत्ति की कोई गुंजाइश नहीं होगी और यह ऊपर वर्णित विशिष्ट परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ है, हम भारत सरकार को निर्देश देते हैं कि वह बिना सुने दिए गए हमारे आदेश को समझदारी से ले और आवश्यक प्रावधान करे। हम भारतीय चिकित्सा परिषद को आवश्यकताओं में छूट देकर आवश्यक आवास उपलब्ध कराने का भी सुझाव देते हैं। इन्हें शीघ्रता से किया जा सकता है ताकि समय सारिणी प्रभावित न हो।

एन.पी.वी. याचिकाएं निस्तारित की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।